भारत स्थिरीकरण निधि के साथ कार्बन ट्रेडिंग बाजार को मजबूत करेगा

प्रश्न पत्र- 3 (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

स्रोत- द हिन्दू

- भारत अपने नियोजित कार्बन बाजार में क्रेडिट की कीमतों को एक निश्चित सीमा से ऊपर रखने के लिए एक स्थिरीकरण कोष की योजना बना रहा है जिसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रेडिट की कीमतें निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहें और बाजार उत्सर्जन में कटौती करने में सफल हों।

आज के आलेख में क्या है?

- पृष्ठभूमि
- कार्बन बाजारों के बारे में (अर्थ, प्रकार, भारत में बाजार, विधायी उपाय, आदि)
- सम्पादकीय सारांश

पृष्ठभूमि:

- ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से नीचे रखने के लिए (आदर्श रूप से 1.5°C से अधिक नहीं) वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को इस दशक में 25 से 50% तक कम करने की आवश्यकता है।
- 2015 के पेरिस समझौते के भाग के रूप में अब तक लगभग 170 देशों ने अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत किया है, जिसे वे हर पांच साल में अपडेट करने पर सहमत हुए हैं।
- NDCs शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने वाले देशों द्वारा जलवायु प्रतिबद्धताएँ हैं।
- उदाहरण के लिए, भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप पर कार्य कर रहा है।
- अपने NDC को पूरा करने के लिए, एक शमन रणनीति- कार्बन बाजार कई देशों में लोकप्रिय हो रही है।
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में देशों द्वारा अपने NDC को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के उपयोग का प्रावधान है।

कार्बन बाजार क्या हैं?

- कार्बन बाजार अनिवार्य रूप से कार्बन उत्सर्जन पर कीमत तय करने का एक उपकरण है जिससे एक व्यापारिक प्रणाली स्थापित होती हैं जहाँ कार्बन क्रेडिट या भत्ते खरीदे और बेचे जा सकते हैं।
- कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने, कम करने या अलग करने के बराबर होता है।
- इस बीच, कार्बन भत्ते या कैप, देशों या सरकारों द्वारा उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।
- इस साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कार्बन बाजारों में रुचि बढ़ रही है,

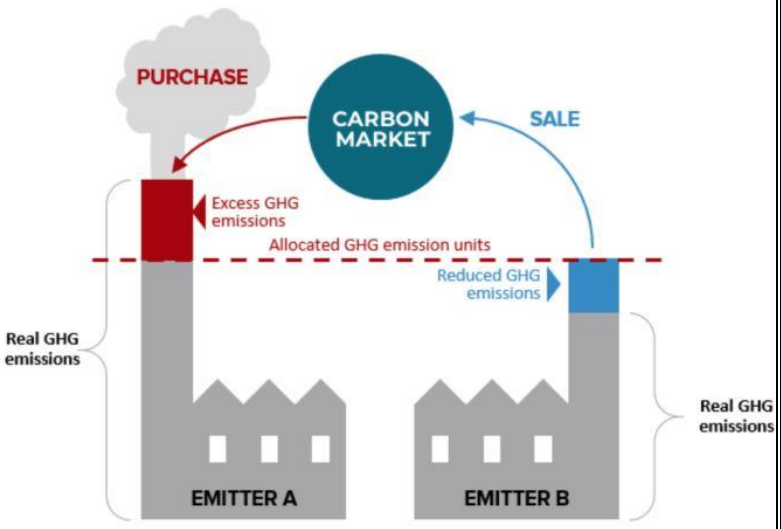

यानी देशों द्वारा प्रस्तुत एनडीसी के 83% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तंत्र का उपयोग करने का के इरादे का उल्लेख किया गया है।

कार्बन बाज़ार दो प्रकार के होते हैं :

अनुपालन बाजार -

- ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो आधिकारिक तौर पर विनियमित होते हैं।
- इस क्षेत्र की संस्थाओं को उनके द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन के बराबर वार्षिक भत्ते या परमिट जारी किए जाते हैं।
- यदि कंपनियाँ सीमित मात्रा से अधिक उत्सर्जन का उत्पादन करती हैं, तो उन्हें या तो आधिकारिक नीलामी के माध्यम से या उन कंपनियों से अतिरिक्त परमिट खरीदना पड़ता है, जिन्होंने अपने उत्सर्जन को सीमा से नीचे रखा है, उन्हें अतिरिक्त भत्ते के साथ छोड़ दिया जाता है।
- कार्बन का बाजार मूल्य बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किया जाता है जब खरीदार और विक्रेता उत्सर्जन भत्ते में व्यापार करते हैं।

स्वैच्छिक बाजार –

- ये ऐसे बाजार हैं जिनमें उत्सर्जक; जैसे - निगम, निजी व्यक्ति और अन्य, एक टन CO2 या समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं।
- इस तरह के कार्बन क्रेडिट विभिन्न गतिविधियों द्वारा बनाए जाते हैं जो हवा से CO2 को कम करते हैं, जैसे कि वनीकरण।

- एक स्वैच्छिक बाजार में, एक निगम अपने अपरिहार्य GHG उत्सर्जन की भरपाई करने की तलाश में उन परियोजनाओं में लगी इकाई से कार्बन क्रेडिट खरीदता है जो उत्सर्जन को कम करने में लगी हुई हैं।

भारत में कार्बन बाजार:

- अतीत में, भारत ने कार्बन क्रेडिट के उत्पादन और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों को निर्यात करने में निवेश किया है।
- 2010 और जून, 2022 के बीच, भारत ने 35.94 मिलियन कार्बन क्रेडिट या वैश्विक स्तर पर जारी सभी स्वैच्छिक कार्बन मार्केट क्रेडिट का लगभग 17% जारी किया।
- हालांकि, सरकार अब इसके निर्यात पर रोक लगाने, कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्थानीय घरेलू बाजार के विस्तार की गारंटी देने और अपने आंतरिक व्यापार को बढ़ाने का इरादा रखती है।
- वर्तमान में, भारत का कार्बन बाजार एक स्वैच्छिक कार्बन बाजार है जहाँ निजी पार्टियां स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट के लिए वातावरण से GHG की प्रमाणित कटौती का आदान-प्रदान करती हैं।

विधायी पहल :

- लोकसभा ने अगस्त, 2022 में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने और देश में कार्बन बाजारों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना था।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत के कार्बन बाजार को विकसित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना है।
- यह विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है। संस्थाएं प्रमाण-पत्र खरीदने या बेचने की हकदार होंगी।

सम्पादकीय सारांश:

- भारत अपने नियोजित कार्बन बाजार में क्रेडिट की कीमतों को एक निश्चित सीमा से ऊपर रखने के लिए एक स्थिरीकरण निधि की योजना बना रहा है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्बन क्रेडिट की कीमतें निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहें और बाजार उत्सर्जन में कटौती करने में सफल हो।
- 2008 की शुरुआत में आर्थिक संकट के कारण, अन्य देशों में कार्बन क्रेडिट की कीमतों में भारी गिरावट आई क्योंकि सरकारों ने उनमें से अधिकांश जारी किए थे।
- यदि कीमतें बहुत कम गिरती हैं तो स्थिरीकरण निधि में धन का उपयोग बाजार नियामक द्वारा कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए किया जाएगा।
- यह कैसे काम करेगा और पैसा कहां से आएगा, इस पर अभी भी चर्चा चल रही है।
- विश्व बैंक पहले ही कह चुका है कि वह भारत को कार्बन-मूल्य निर्धारण उपकरण तैयार करने में मदद करने के लिए $8 मिलियन प्रदान करेगा।
- सरकार की प्रस्तुति स्लाइड के अनुसार, भारत का कार्बन बाजार दो चरणों में स्थापित किया जा रहा है।
- पहले चरण में 2023 से 2025 के बीच मौजूदा ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्रों को कार्बन क्रेडिट में बदला जाएगा।

❁ उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही कार्बन बाजार के नियमों को प्रकाशित करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्र. कार्बन बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है।
2. कार्बन बाजार केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(b) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 , न ही 2

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न- कार्बन बाजार क्या है? कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए भारत में कार्बन बाजार के ढांचे की क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)